नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 065
दि. 07.12.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

बाबरी मुद्दे पर फिर सियासी गर्मी: हुमायूं कबीर के बयान से तनाव बढ़ा, विहिप ने ममता सरकार को चेताया

(जीएनएस)। नई दिल्ली की दोपहर में जैसे ही खबर आई कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है, राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। पिछले कई वर्षों से देश राम जन्मभूमि विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णय के बाद स्थिरता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन कबीर के बयान ने मानो पुराने जख्म कुरेद दिए। यही कारण है कि विश्व हिंदू परिषद ने इस पूरे प्रकरण को केवल एक 'विवादित बयान' नहीं माना, बल्कि राज्य की सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव पर गंभीर खतरा बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी।

विहिप की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कड़े शब्दों में कहा कि कबीर बाबरी मस्जिद का बहाना बनाकर राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार यह केवल एक टिप्पणी नहीं बल्कि एक राजनीतिक रणनीति है, जो मुसलमान और हिंदू समुदाय के बीच अविश्वास की खाई गहरा सकती है। बंसल का कहना है कि मुर्शिदाबाद में कुछ ही महीने पहले अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएँ हुई थीं, जिनकी यादें अभी पूरी तरह धुंधली भी नहीं हुई हैं; ऐसे में कबीर जैसे नेता का इस प्रकार का बयान देना किसी सोची-समझी साजिश जैसा प्रतीत होता है। विहिप का आरोप है कि कबीर राज्य में कट्टरपंथी समूहों को सक्रिय कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं और यह सीधे-सीधे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवमानना भी है।

राजनीतिक बयानबाज़ी से इतर, इस पूरे प्रकरण का सबसे चिंताजनक पहलू वही है जिस पर विहिप ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि बाबरी मस्जिद के नाम पर कहीं भी तनाव बढ़ता है, हिंसा फैलती है या साम्प्रदायिक माहौल बिगड़ता है, तो इसकी जिम्मेदारी केवल कबीर पर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर भी होगी। संगठन ने कहा कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने निलंबित नेता की गतिविधियों पर नजर रखे और समय रहते हस्तक्षेप करे, ताकि किसी भी क्षेत्र में हालात नियंत्रण से बाहर न हों।

विहिप ने अपने बयान में यह मुद्दा भी उठाया कि पश्चिम बंगाल लंबे समय से अवैध घुसपैठ, सीमा पार से आने वाले कट्टरपंथी प्रभाव और सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं से जूझ रहा है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में समय-समय पर होने वाली घटनाएँ इस चिंता को और गहरा करती हैं। परिषद की दलील है कि ऐसे माहौल में बाबरी मस्जिद जैसे संवेदनशील मुद्दे को फिर से राजनीतिक मंच पर लाना आग में घी डालने जैसा है, और यदि स्थिति बिगड़ती है तो इसका असर केवल राज्य तक सीमित नहीं रह सकता।

इसी चिंता को देखते हुए विहिप ने न केवल राज्य सरकार बल्कि राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी तुरंत हस्तक्षेप की अपील की है। संगठन का कहना है कि यदि प्रशासन अभी कदम नहीं उठाता तो यह मुद्दा देखकर-देखते भड़क सकता है। उधर स्थानीय प्रशासन पहले ही बेलडांगा और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा चुका है। पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात कर दी गई हैं और खुफिया विभाग को हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया है। हालांकि अभी तक कोई बड़ा तनाव सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ तेज़ हो रही हैं उससे हालात और अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।

मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिंतित हैं। स्थानीय नागरिकों को डर है कि यदि राजनीतिक बयानबाज़ी इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में चुनावी माहौल के साथ-साथ साम्प्रदायिक तनाव भी बढ़ सकता है। कई लोगों का मानना है कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद को सदा के लिए सुलझा दिया है, उसे फिर से हवा देना किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं। इसी बीच राजनीतिक दल भी अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर बहसें और तेज़ हो गई हैं।

फिलहाल, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन बयानबाज़ी ने जिस तरीके से पुराने घावों को फिर से ताजा कर दिया है उससे यह साफ है कि यह मुद्दा अभी शांत होने वाला नहीं। विहिप का रुख बेहद सख्त है और सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है कि वह कबीर के बयान पर जल्द और निर्णायक कदम उठाए। आने वाले दिनों में यह मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक और विवादास्पद केंद्र बन सकता है, और जनता की उम्मीदें इसी पर टिकी हैं कि सरकार, प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संगठन मिलकर माहौल को शांत और स्थिर रखें।

भारत बना स्टार्टअप में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र, विज्ञान और नवाचार में बढ़ रही वैश्विक पहचान

(जीएनएस)। पंचकूला में शनिवार को विज्ञान और नवाचार का उत्सव देखने को मिला, जब केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल (IISF) के 11वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए देश की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है, और इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण देश के स्टार्टअप सेक्टर की सफलता है। भारत अब 1.75 लाख स्टार्टअप के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुँच चुका है, जो नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में देश की ताकत को दर्शाता है।

डॉ. सिंह ने बताया कि पेटेंट फाइलिंग में भारत की हिस्सेदारी अब 56 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है, और वैज्ञानिक प्रकाशनों के क्षेत्र में भी देश का योगदान लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत से 1.91 लाख शोध प्रकाशन सामने आ चुके हैं, और अगले दो वर्षों में यह आंकड़ा अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। उनके अनुसार, यह सब तभी संभव हो पाया है जब विज्ञान और तकनीक को जन-जन तक पहुँचाने के लिए प्रभावी नीतियाँ और मंच उपलब्ध कराए गए।

IISF के उद्घाटन समारोह में उन्होंने इसे '3C—उत्सव, संचार और करियर' का अनोखा संगम बताते हुए कहा कि यह महोत्सव विज्ञान को सरल रूप में जनता तक पहुँचाने और नई पीढ़ी को करियर और शोध के अवसर दिखाने का बेहतरीन माध्यम है। चार दिवसीय इस महोत्सव में न केवल विज्ञान इस तरह के आयोजन शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और छात्रों को नए विचारों और नवाचारों से जोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। 6 से 9 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में प्रदर्शनियाँ, बिजनेस मीटिंग, प्रतियोगिताएँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जो इसे एक संपूर्ण विज्ञान और नवाचार उत्सव बनाते हैं।

डॉ. सिंह ने कहा कि विज्ञान और स्टार्टअप सेक्टर में भारत की प्रगति सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह देश की युवा शक्ति, अनुसंधान क्षमता और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी का प्रमाण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भारत नवाचार के क्षेत्र में और ऊँचाइयाँ छुएगा और स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व स्तर पर और मजबूती से स्थापित होगा।

इस अवसर पर उपस्थित शोधकर्ता, उद्यमी और छात्रों ने भी उत्सव की भव्यता और विज्ञान के लोकप्रियरण के प्रयासों की सराहना की। IISF ने साबित कर दिया कि भारत में स्टार्टअप और विज्ञान दोनों ही तेजी से विकसित हो रहे हैं और देश वैश्विक नवाचार मानचित्र पर एक मजबूत पहचान बनाने में सक्षम है।

सरकार की सख्त कार्रवाई: इंडिगो संकट के बीच आसमान छूते किरायों पर रोक, नई सीमा लागू

(जीएनएस)। नई दिल्ली की रात में जब अधिकांश लोग दिनभर की थकान से राहत तलाश रहे थे, उसी समय इंडिगो की उड़ानों में उत्पन्न भारी अव्यवस्था ने हज़ारों यात्रियों की नींद उड़ा दी थी। एयरपोर्ट के गेटों के बाहर बेकाबू भीड़, टिकट काउंटर पर लंबी कतारें और ऑनलाइन पोर्टलों पर अचानक बढ़े हुए किराए ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। कई मार्गों पर किराया इतना बढ़ गया कि सामान्य दिनों में चार हजार रुपये में मिलने वाली टिकट बीस से पच्चीस हजार तक पहुँच गई। सोशल मीडिया पर गुस्से और असंतोष की इस लहर ने सरकार को तुरंत हरकत में ला दिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय पहले से इंडिगो के तकनीकी संकट से उत्पन्न देशव्यापी प्रभाव का विश्लेषण कर रहा था। इंडिगो के बेड़े का बड़ा हिस्सा कुछ दिनों से तकनीकी दिक्कतों और स्टाफिंग मुद्दों से जूझ रहा था, जिसके चलते उड़ानें या तो रद्द हो रही थीं या घंटों विलंब से चल रही थीं। यह स्थिति अचानक देश के सबसे बड़े घरेलू एयरलाइन नेटवर्क में एक बड़ी खाई पैदा कर गई, जिसका फायदा उठाने में अन्य एयरलाइनों ने देर नहीं लगाई। अप्रत्याशित रूप से बढ़े हुए किराए ने यात्रियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा कर दिया। किसी को किसी पारिवारिक आपात स्थिति में तत्काल उड़ान लेनी थी, तो किसी छात्र को परीक्षा देने जाना था—लेकिन आसमान छूते किरायों ने हर किसी की राह रोक दी।

सरकार ने स्थिति की गंभीरता देखते हुए शनिवार को अब तक का सबसे निर्णायक कदम उठाया। मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया कि प्रभावित मार्गों पर हवाई किराये की ऊपरी सीमा तय कर दी गई है और कोई भी कंपनी इसे पार नहीं कर सकेगी। यह निर्णय तुरंत लागू कर दिया गया और इसके बाद ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ ही घंटों में किराये स्थिर होने लगे। मंत्रालय ने साफ कहा कि यह व्यवस्था अस्थायी है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा और हितों को देखते हुए यह कदम आवश्यक था। जैसे ही इंडिगो अपनी सेवाओं को सामान्य स्थिति में वापस ले आएगा—यह नियंत्रण स्वतः समाप्त हो जाएगा।

इस कदम का सबसे संवेदनशील पहलू यात्रियों की प्राथमिक श्रेणियों पर विशेष ध्यान देना है। वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, चिकित्सकीय कारणों से यात्रा कर रहे लोगों और दिव्यांग यात्रियों के टिकटों और सहायता व्यवस्थाओं पर मंत्रालय ने विशेष निगरानी शुरू कर दी है। एयरपोर्ट प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि वे सहायता डेस्क, व्हीलचेयर सेवाएँ, मेडिकल इमरजेंसी यूनिट और सूचना प्रसारण को अधिक सशक्त बनाएं, ताकि यात्रियों को किसी भी स्तर पर दिक्कत न हो।

किरायों की निगरानी को लेकर सरकार ने इस बार तकनीकी स्तर पर भी एक बड़ा बदलाव किया है। रियल-टाइम डेटा मॉनिटरिंग की नई व्यवस्था के तहत मंत्रालय एयरलाइनों और टिकटिंग प्लेटफॉर्म से हर मिनट अपडेट होने वाला किराया डेटा प्राप्त करेगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी एयरलाइन यदि तय सीमा से ऊपर किराया लगाने की कोशिश भी करती है, तो वह तुरंत सरकारी रडार पर आ जाएगी। मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी—चाहे वह जुर्माना हो या संचालन पर प्रतिबंध।

एविएशन विशेषज्ञ इस कदम को संकट की घड़ी में बाजार को स्थिर बनाने वाला कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि भारत का एविएशन बाजार तेजी से बढ़ रहा है और ऐसी अस्थिरताएँ यात्री भरोसे को गहरा नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसलिए सरकार का समय पर हस्तक्षेप न सिर्फ आवश्यक था, बल्कि यात्रियों के लिए राहत का संदेश भी है।

इंडिगो की उड़ानों के सामान्य होने में कितना समय लगेगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन फिलहाल देश के यात्रियों ने राहत की एक बड़ी सांस जरूर ली है। सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि संकट के समय आसमान का खेल सिर्फ एयरलाइनों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। जब चारों तरफ अनिश्चितता थी, तब यही कदम उन हज़ारों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बना है जो मजबूरी में यात्रा करना चाहते थे, मगर मनमानी कीमतों ने उनकी उड़ान को रोक दिया था।

क्वाड देशों का दो टूक संदेश: सीमा-पार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं, इंडो-पैसिफिक सुरक्षित बनाने की प्रतिबद्धता

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने क्वाड मंच के जरिए एक बार फिर आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है और विशेष रूप से सीमा-पार आतंकवाद पर अपनी गहरी चिंता जताई है। चारों देशों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित, स्वतंत्र और आतंकवाद-मुक्त बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही बहुपक्षीय सहयोग और सूचनाओं के तेज आदान-प्रदान पर जोर दिया।

नई दिल्ली में 4–5 दिसंबर को आयोजित तीसरी क्वाड काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप (CTWG) बैठक में सदस्य देशों ने आतंकवादियों और उनके नेटवर्क से जुड़ी सूचनाओं के साझा प्रवाह को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। यह बैठक भारत की अगुवाई में आयोजित अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की तैयारियों का भी हिस्सा थी। संयुक्त बयान में स्पष्ट किया गया कि क्वाड देश आतंकवादियों, आतंकी संगठनों और उनके समर्थकों से जुड़ी सूचनाओं को निरंतर साझा करेंगे और वैश्विक सुरक्षा ढांचे में अपने योगदान को और मज़बूत करेंगे।

बैठक में भारत के सेक्रेटरी (वेस्ट) और राजदूत सिबी जॉर्ज ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साझा राजनीतिक इच्छाशक्ति और गहन सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति क्वाड देशों द्वारा दिखाए गए समर्थन के लिए भी आभार जताया। क्वाड सदस्यों ने 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और इसके साजिशकर्ताओं तथा वित्तपोषकों को न्याय के दायरे में लाने की अपील की। साथ ही सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से आतंकवाद-रोधी सहयोग बढ़ाने का अनुरोध किया गया।

बैठक में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र समेत वैश्विक आतंकवाद की मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन किया गया और उभरती चुनौतियों से निपटने के उपाय तलाशे गए। विशेष रूप से "शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद-रोधी कार्रवाई" पर टेबलटॉप अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने साझा रणनीतियों और सहयोगी उपायों पर चर्चा की। भारत ने सितंबर 2025 में क्वाड की दो महत्वपूर्ण कार्यशालाओं की मेजबानी भी की थी, जिसमें ड्रोन के माध्यम से होने वाली आतंकी गतिविधियों और नई तकनीकों से आतंकी वित्तपोषण रोकने पर विचार-विमर्श हुआ।

क्वाड देशों ने आतंकवाद-रोधी साझेदारी को और मज़बूत करने का संकल्प लिया और 2026 में अगली CTWG बैठक आयोजित करने पर सहमति जताई। इस बैठक ने साफ संदेश दिया कि क्वाड सदस्य राष्ट्र इंडो-पैसिफिक और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हैं और सीमा-पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नीरव मोदी प्रत्यर्पण मामला CBI-ED की टीम लंदन जाएगी भारत लाने की प्रक्रिया में तेजी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने की दिशा में सरकार ने अगले सप्ताह निर्णायक कदम उठाने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की संयुक्त टीम अगले हफ्ते लंदन का दौरा करेगी। यह टीम नीरव मोदी की प्रत्यर्पण याचिका की पहली सुनवाई में हिस्सा लेकर क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) को उसके दावों का जवाब देने में मदद करेगी।

एजेंसियों का कहना है कि नीरव मोदी द्वारा उठाए गए दावे—जैसे कि भारत लाए जाने पर उसे यातना का खतरा है—वास्तविकता से कोसों दूर हैं। भारत सरकार ने उसकी सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए हैं और प्रत्यर्पण के दौरान उसे केवल न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना होगा। CBI और ED की टीम नीरव मोदी की हर दलील का कड़ा जवाब अदालत में पेश करेगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि नीरव मोदी अक्सर प्रत्यर्पण प्रक्रिया को रोकने के लिए अपील करता रहा है, और ब्रिटेन की अदालतों ने इससे पहले कई बार उसकी याचिकाएँ खारिज की हैं। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि लंदन की अदालत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे सकती है और उसे भारत लाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

नीरव मोदी ने अगस्त में वेस्टमिंस्टर कोर्ट में अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि भारत प्रत्यर्पण के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा उसे कठोर पूछताछ और यातना का सामना करना पड़ सकता है। इस पर भारत सरकार ने लंदन को आश्वासन पत्र भेजा है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्यर्पण की स्थिति में नीरव मोदी केवल मुकदमे का सामना करेगा और किसी भी एजेंसी द्वारा उसे हिरासत में नहीं लिया जाएगा।

जांच अधिकारियों के अनुसार, यह दौरा नीरव मोदी की याचिका पर भारत के पक्ष को मजबूती से पेश करने का अवसर है। CBI और ED की टीम न केवल उसके दावों का खंडन करेगी, बल्कि अदालत को यह भी बताएगी कि नीरव मोदी की पूर्व याचिकाओं को ब्रिटिश न्यायपालिका ने पहले ही खारिज कर दिया है। इस मामले में प्रत्यर्पण मंजूर होने पर भारत सरकार उसे जल्द ही देश में लाने की प्रक्रिया शुरू कर देगी।

विश्लेषकों का कहना है कि नीरव मोदी मामला केवल एक उच्च प्रोफ़ाइल वित्तीय अपराध केस नहीं है, बल्कि यह भारत की अंतरराष्ट्रीय न्यायिक साझेदारी और विदेशों में न्यायिक सहयोग की क्षमता को भी परखने वाला मामला बन गया है। आगामी लंदन दौरे के दौरान तय होगा कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है और नीरव मोदी भारत लौटता है या नहीं।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

बीएलओ पर कार्य का दबाव कम किया जाए

मतदाता सूचियों की शुद्धता व पारदर्शी चुनावों के लिये चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश देकर देश की शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को राहत ही दी है। वहीं दूसरी ओर संसद से सड़क तक एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगे विपक्ष को इस निर्णय से बैकफुट पर आना पड़ेगा। दरअसल, विपक्षी दल बिहार में शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार मुखर विरोध करते रहे हैं और मामला कई बार अदालत तक भी पहुंचा था। लेकिन बिहार में बहुत कम समय में यह काम पूरा हुआ और राज्य में नई सरकार भी चुन ली गई है। हालिया प्रक्रिया की कथित विसंगतियों के बाबत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारों के कर्मचारी एसआईआर व अन्य वैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिये बाध्य हैं। वहीं कोर्ट ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिए हैं कि एसआईआर में लगे बूथ लेवल अधिकारियों पर काम का दबाव कम करने के लिए तुरंत कदम उठाएं। इसके लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण में लगे कई बीएलओ के तनाव से मरने व आत्महत्या करने के समाचार आए थे। जिसके चलते चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को एक सप्ताह के लिये आगे बढ़ाया था। वहीं दूसरी ओर अदालत ने स्पष्ट किया कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती। यह भी कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके पास मतदाता सूचियों में पारदर्शिता लाने के लिये एसआईआर को अंजाम देने के संवैधानिक व कानूनी अधिकार हैं। साथ ही अदालत ने इस प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक लगाने से इनकार किया। इसके अलावा अदालत का कहना था कि यदि भविष्य में किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे।

निस्संदेह, विगत में भी देश में समय-समय पर मतदाता सूचियों में पुनरीक्षण का कार्य होता रहा है। लेकिन यह कभी इतना बड़ा राजनीतिक विरोध का मुद्दा नहीं बना। बहरहाल, अदालत के इस आदेश के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण को मुद्दा बनाकर विरोध करने वाले राजनीतिक दलों को झटका अवश्य लगा होगा। हालांकि, इससे पहले भी अदालत ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया था। साथ ही उससे जुड़ी विसंगतियों को दूर करने को जरूरी निर्देश अवश्य दिए थे। जहां तक बूथ लेवल अधिकारियों पर काम के दबाव का सवाल है तो निश्चित ही यह एक श्रम साध्य कार्य है। इस काम में लगे शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े दस्तावेजों के प्रमाणीकरण और शिकायतों के निवारण में खासी माथापच्ची करनी पड़ती है। इसलिए बीएलओ के काम के बोझ को कम करने का प्रयास करना बेहद जरूरी है। जिसके लिये कर्मचारियों की संख्या तुरंत बढ़ाने की जरूरत है, जिससे बीएलओ का काम का बोझ कम हो सके। उन्हें साप्ताहिक अवकाश लेने का अवसर मिल सके। निस्संदेह, सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन नियुक्त कर्मचारियों के लिये अपरिहार्य है। ऐसी ही जटिलता का सामना कर्मचारियों को जनगणना आदि कार्यक्रमों व स्वास्थ्य से जुड़े मिशनों में करना पड़ता है। घर-घर जाना और लोगों की तल्ख प्रतिक्रियाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों का भी दायित्व है कि वे अपने दल के बूथ स्तरीय अधिकारियों को बीएलओ की मदद करने को प्रेरित करें। महज सत्ता पक्ष की नीतियों के विरोध के लिये विरोध करना स्वस्थ लोकतंत्र के हित में नहीं कहा जा सकता। विपक्ष को लोकतंत्र के हित में विरोध के साथ रचनात्मक सहयोग भी करना चाहिए। लोकतंत्र को संबल देने वाली विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को सफल बनाने में जहां सरकारी कर्मचारियों की बड़ी भूमिका है, वहीं राजनीतिक दलों व आम नागरिकों के भी दायित्व हैं। नागरिकों को राष्ट्रीय कार्यों में नागरिक धर्म का भी निर्वाह करना चाहिए। आम लोगों की सजगता व सक्रियता बूथ लेवल अधिकारियों के बोझ को कुछ कम जरूर कर सकती है।

मनमानी की शर्मनाक कहानी, अक्षम हो गया डीजीसीए

> देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने डीजीसीए के नए नियमों का पालन न करके यात्रियों को बहुत परेशान किया। नियमों का उद्देश्य पायलटों को थकान से बचाना था, लेकिन इंडिगो ने लापरवाही बरती। उड़ानों के रद्द होने और देरी से चलने के कारण यात्रियों को समय और धन का नुकसान हुआ। इंडिगो को इसके लिए मुआवजा देना चाहिए। सरकार को इससे सबक लेना चाहिए।

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने भारतीय यात्रियों को पिछले एक सप्ताह में जितना अधिक परेशान किया, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इंडिगो के यात्रियों को इसलिए परेशान होना पड़ा, क्योंकि उसने सुरक्षित विमान यात्रा के लिए नागरिक विमानों के संचालन की नियामक संस्था डीजीसीए के नए नियमों का पालन करने की कोई तैयारी नहीं कर रखी थी।

ये नियम अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत बनाए गए थे और सभी एयरलाइंस को उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पायलट एक निश्चित समय से अधिक ड्यूटी न करें। सुरक्षित विमान यात्रा के लिए यह आवश्यक होता है कि पायलट लंबी ड्यूटी के चलते थकान का शिकार न हों।

पायलटों को थकान से बचाने के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए जहां एअर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा एयरलाइन ने पर्याप्त व्यवस्था की, वहीं इंडिगो ने ऐसा कुछ करना आवश्यक नहीं समझा और वह भी तब, जब नए नियम लागू करने की समयसीमा बढ़ाई गई थी। इससे यही पता चलता है कि इंडिगो नए नियम लागू करने के लिए तैयार ही नहीं थी।

डीजीसीए को इसकी निगरानी करनी चाहिए थी कि इंडिगो समेत सभी एयरलाइंस नए नियमों का पालन करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था कर रही हैं या नहीं? उसे इंडिगो पर इसलिए अधिक निगाह रखनी चाहिए थी, क्योंकि वह घरेलू विमान सेवा की सबसे बड़ी एयरलाइन है और उसकी हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक है।

जहां डीजीसीए ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया, वहीं इंडिगो ने भी उसे यह सूचित करना आवश्यक नहीं समझा कि वह नए नियमों का पालन करने की स्थिति में नहीं है या फिर उसे पायलट और अन्य कर्मचारी भर्ती करने के लिए कुछ और मोहलत दी जाए। चूंकि डीजीसीए ने सजगता नहीं बरती, इसलिए

जब 1 दिसंबर से नए नियम लागू हुए तो इंडिगो की उड़ानें या तो रद होने लगीं या फिर विलंब से चलने लगीं।

चूंकि रद और विलंब से चलने वाली उड़ानों की संख्या सैकड़ों में पहुंचने लगी, इसलिए परेशान होने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ने लगी। बड़ी संख्या में इंडिगो की उड़ानें रद होने से हवाई किराया भी महंगा होने लगा। हजारों विमान यात्री केवल समय पर अपने गंतव्य तक ही नहीं पहुंच सके, बल्कि उन्हें अतिरिक्त किराया भी देना पड़ा। इसका केवल आकलन ही नहीं किया जाना चाहिए कि डीजीसीए और इंडिगो की ढिलाई के कारण लोगों के समय और धन की कितनी बर्बादी हुई, बल्कि उसका भुगतान भी किया जाना चाहिए।

इसके लिए किसी को अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं कि इंडिगो केवल खेद जताकर कर्तव्य की इतिश्री कर ले। यदि उसे यात्रियों के समय और धन की बर्बादी की भरपाई के लिए विवश नहीं किया गया तो उसका रवैया सुधरना कठिन ही है।

इंडिगो को किसी न किसी स्तर पर दंड का भागीदार इसलिए भी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उसने एक तरह से जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं, जिससे यात्रियों को परेशान होना पड़ा और साथ ही डीजीसीए को नए नियम लागू करने के अपने ऐसे फैसले को वापस लेना पड़ा, जो विमान यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। डीजीसीए को इसका आभास होना चाहिए कि एक नियामक संस्था के रूप में उसकी क्षमता और साख पर गंभीर सवाल उठे हैं।

भारतीय विमानन बाजार इस समय विश्व का तीसरे नंबर का बड़ा बाजार है। विमान यात्री इंडिगो और एअर इंडिया पर ही अधिक निर्भर हैं। यह साफ दिखा कि इंडिगो ने डीजीसीए को दबाव में लेने की रणनीति पर काम किया और जानबूझकर जरूरत से ज्यादा उड़ानें रद कीं। इसका कारण अपने मुनाफे की अधिक चिंता करना ही रहा होगा। निःसंदेह हर कंपनी को अपने मुनाफे की चिंता करने का अधिकार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई कंपनी बाजार में अपने एकाधिकार वाली स्थिति का बेजा लाभ उठाकर नियामक संस्था के उन नियम-कानूनों का भी पालन न करे, जो लोगों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं।

इंडिगो चाहती तो डीजीसीए के नए नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक पायलट और कर्मचारी आसानी से भर्ती कर सकती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने यह मान लिया कि डीजीसीए उस पर एक सीमा से अधिक दबाव नहीं डाल पाएगा। सच जो भी हो, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि डीजीसीए को नए नियमों पर अमल को दो माह के लिए टालना पड़ा है। इससे देश-दुनिया को यही संदेश जाएगा कि भारत सुरक्षित विमान संचालन के प्रति सतर्क नहीं।

इंडिगो के मामले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह पहले भी यात्रियों की सुख-सुविधा का ध्यान न रखने के जानी जाती रही है। इंडिगो से यात्रा करने वालों को यह शिकायत रहती है कि उसके संचालक दल के सदस्य उनसे रूखा व्यवहार करते हैं और वैसी कोई रियायत नहीं देते, जैसी अन्य एयरलाइंस दे देती हैं। इन शिकायतों के बाद भी विमान यात्री इंडिगो से यात्रा करना इसलिए पसंद करते थे, क्योंकि उनका परिचालन समय पर होता था।

इसी के चलते एविएशन बाजार में इंडिगो की हिस्सेदारी बढ़ती गई, लेकिन यही बढ़ी हुई हिस्सेदारी अब एक समस्या के रूप में उभर आई। डीजीसीए कुछ भी दावा करे, इंडिगो ने नए नियमों को लागू करने के बजाय अपनी उड़ानों को स्थगित करके केवल लोगों को परेशान ही नहीं किया, बल्कि एक तरह से उसे झुकने के लिए भी बाध्य किया। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं कि कोई कंपनी बाजार में अपनी अधिक हिस्सेदारी के सहारे मनमानी करे और यहां तक कि नियामक संस्था को अपना एक जरूरी फैसला लागू करने में अक्षम कर दे।

भले ही नागरिक उड्डयन मंत्री यह कह रहे हों कि सुरक्षा से समझौता किए बिना विमान संचालन संबंधी नए नियमों को स्थगित करने का फैसला किया गया है, लेकिन तथ्य तो यही है कि पायलटों को कम आराम के साथ विमानों का संचालन करना पड़ेगा। इंडिगो के रवैये के कारण जो संकट खड़ा हुआ, उससे सरकार को सबक लेना होगा और यह देखना होगा कि नए विमान खरीद रहीं एयरलाइन को विमान संचालन की अनुमति तभी मिले, जब वे जरूरी नियमों का पालन करने में सक्षम दिखें।

प्रेरणा

अदम्य इच्छा की यात्रा

कभी यूरोप के एक छोटे से कस्बे में एक बालक जन्मा, जिसका नाम था अल्बर्ट। यह बालक शुरुआत से ही कुछ शांत, कुछ अंतर्मुखी और कुछ अलग था। वह दुनिया को वैसे नहीं देखता था जैसे बाकी लोग देखते थे। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों की आवाज़ों और खेल की धुन में खोए रहते, यह बालक किसी तारों को ताकता, कभी दीवार पर पड़ती रोशनी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता, तो कभी सोच में डूबकर बैठ जाता कि यह दुनिया आखिर चल कैसे रही है। लोग उसके इस अजीब से स्वभाव को अक्सर उसकी कमजोरी मान लेते। उसकी धीमी प्रतिक्रिया और कम बोलने की आदत के कारण कई लोगों को लगता कि वह बाकी बच्चों जितना समझदार नहीं है।

समय के साथ वह स्कूल जाने लगा, लेकिन स्कूल उसके लिए आसान नहीं था। विशेषकर गणित उसके लिए किसी दानव की तरह था। सवालों को देखते ही उसकी गर्दन झुक जाती, हाथ काँपने लगते और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। अध्यापक कठोर शब्दों में कहते—"अल्बर्ट, इतने सरल प्रश्न भी नहीं होते तुमसे? ऐसे कैसे चलेगा?" उसके सहपाठी उसकी किताबें छीनकर छेड़ते, उसे नामों से बुलाते, और कहते—"बेवकूफ है, गणित तो कभी समझेगा ही नहीं।" यह उपहास किसी छोटे से पौधे पर पड़ते ठंडे झोंकों जैसा था, जो उसके आत्मविश्वास को बार-बार मुरझा देता।

घर लौटकर वह अक्सर अपनी कॉपी खोलता और उन सवालों को देख-देखकर आह भरता। कोई भी गणितीय चिह्न उसके लिए एक पहेली से अधिक डरावना लगता। रात को जब सब सो जाते, वह अपने कमरे की खिड़की से आसमान देखता और सोचता कि क्या वह सच में उतना ही अयोग्य है जितना लोग कहते हैं। उसे लगता कि शायद उसके जीवन में कोई दिशा नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई उम्मीद नहीं। वह रोना चाहता, लेकिन आँसू भी जैसे उसके गले में अटक जाते।

एक दिन, जब वह अपनी कॉपी की पन्नियों को पलटते-पलटते थक गया, तभी उसके पिता उसके पास आकर शांत स्वर में बोले—"बेटा, पहाड़ ऊँचे इसलिए लगते हैं क्योंकि हम उन्हें दूर से देखते हैं। जब कोई आदमी पहला कदम रख देता है, तो पहाड़ की ऊँचाई धीरे-धीरे बराबर हो जाती है।" यह एक सरल वाक्य था, लेकिन इन शब्दों ने उसके भीतर जैसे कोई छिपा हुआ दरवाज़ा खोल दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद समस्या गणित की कठिनाई नहीं, बल्कि उसके भीतर का डर है। उसने सोचा—अगर मैं कोशिश ही नहीं करूँगा, तो कैसे जानूँगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं?

अगली सुबह उसने वही किताब उठाई, जो अब तक उसका सबसे बड़ा शत्रु थी। उसने पहला सवाल खोला और खुद से कहा—"इस बार मैं नहीं हारूँगा।" उसने सवाल हल करने की कोशिश की। पहली बार गलत हुआ। दोबारा कोशिश की, फिर गलत हुआ। तीसरी बार भी गलत। लेकिन इस बार उसने किताब बंद नहीं की। उसे कुछ समझ आने लगा कि मेहनत किसी चाबी की तरह है, जो धीरे-धीरे बंद ताले में फिट होती है। उसने लगातार कई घंटे अभ्यास किया। रात हो गई, पर वह रुका नहीं। और जब वही पहला सवाल, जो हमेशा उसे डराता था, आखिरकार हल हो गया, तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से भारी बोझ हटा दिया हो। उसने महसूस किया—"अगर पहला सवाल हो सकता है, तो बाकी भी होंगे। बस मुझे डटे रहना है।"

यही उसका पहला कदम था, जो उसे पूरी जिंदगी आगे ले गया। इसके बाद गणित उसके लिए एक चुनौती नहीं, बल्कि एक खेल बन गया। वह घंटों-घंटों बैठकर सवालों में खो जाता, गलतियाँ उसे परेशान नहीं करतीं बल्कि प्रेरित करतीं कि वह और बेहतर करे। जो समीकरण पहले उसे रुला देते थे, अब उसे रास्ता दिखाने लगे। धीरे-धीरे गणित ने अपने रहस्य खोलने शुरू किए और वह बालक समझने लगा कि हर संख्या, हर सूत्र, हर चिन्ह मानो किसी भाषा की तरह है, जिसे सही अभ्यास से पढ़ा जा सकता है।

वर्ष बीतते गए, और वही बालक जिसने कभी गणित में अनुत्तीर्ण होने का भय झेला था, दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिना जाने लगा। उसने ऐसे सिद्धांत दिए जिन्होंने समय, प्रकाश, ऊर्जा और ब्रह्मांड की परिभाषा ही बदल दी। आज भी दुनिया उसकी सोच पर खड़ी है। उसकी महानता कोई वरदान नहीं थी, कोई चमत्कार नहीं बल्कि रात-रात भर जागकर की गई मेहनत, असंख्य गलतियाँ, अनगिनत पुनः प्रयास, और सबसे बढ़कर उसकी अदम्य इच्छा थी कि वह हार नहीं मानेगा।

कहा जाता है कि एक दिन एक युवक उससे मिलने आया। वह युवक उत्सुक था, प्रेरित था और थोड़ी घबराहट भी थी उसके चेहरे पर। उसने विनम्रता से पूछा—"लोग आपको महान कहते हैं, आपकी बुद्धि की मिसाल देते हैं। कृपया बताइए, महान बनने का असली मंत्र क्या है?" आइंस्टीन मुस्कुराए, जैसे वह प्रश्न पहले भी सुन चुके हों और शांत स्वर में बोले—"अदम्य इच्छा। जब मनुष्य किसी कार्य के प्रति पूरी आत्मा से समर्पित हो जाता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है।" युवक ने चकित होकर पूछा—"क्या सिर्फ इच्छा काफी है?" इस पर आइंस्टीन ने अपनी कहानी सुनाई—कैसे वह भी डरता था, कैसे वह भी असफल होता था, कैसे लोग उसका मज़ाक उड़ाते थे, और कैसे उसने बिना रुके, बिना थके, बिना डरे प्रयास किए।

युवक ने उनकी आँखों में चमक देखी और समझ गया कि महानता कोई ऊँचे आसमान में लटका सितारा नहीं है, बल्कि एक छोटा-सा दीपक है जिसे मनुष्य अपने भीतर जलाता है—लगन का दीपक, इच्छा का दीपक, दृढ़ता का दीपक। उसने आइंस्टीन के चरणों में झुककर आभार व्यक्त किया और लौट गया, पर उसके भीतर नई शुरुआत हो चुकी थी। जहां पहले वह संदेह से भरा था, अब वहाँ साहस था। जहां डर था, अब दृढ़ निश्चय था। वह जान चुका था कि मनुष्य की असली ताकत वही है जो वह कठिनाइयों के समय करता है, न कि आसान दिनों में।

समय पर न्याय मिलने की कोई गारंटी नहीं, लंबित मामलों की बढ़ रही संख्या

यह स्वागतयोग्य तो है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के लिए है और उनकी पहली प्राथमिकता लंबित मामलों को निपटाने तथा मुकदमेबाजी की लागत को कम करने की है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक लंबे समय से एक के बाद एक न्यायाधीशों की ओर से ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है और फिर भी नतीजा ढाक के तीन पात वाला है।

आज की कटु सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। वकीलों की महंगी फीस और तारीख पर तारीख के सिलसिले को देखते हुए आम आदमी के लिए यह संभव नहीं कि वह अपने मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का साहस जुटा सके। यदि वह किसी तरह ऐसा कर भी ले तो समय पर न्याय मिलने की कोई गारंटी नहीं।

यह एक तथ्य है कि निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों की तरह सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश की जनता यह भी अच्छे से देख रही है कि किस तरह कुछ बड़े वकीलों के लिए सब कुछ सुगम होता है। कोई नहीं जानता कि उनके मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर कैसे होने लगती है?

यह पहली बार नहीं जब सुप्रीम कोर्ट के किसी मुख्य न्यायाधीश ने समय पर न्याय देने, लंबित मामलों का बोझ कम करने और मुकदमेबाजी की लागत कम करने की दिशा में कदम उठाने का भरोसा दिलाया हो। यह सिलसिला दशकों से कायम है। हर नया मुख्य न्यायाधीश न्यायिक तंत्र में आमूल-चूल सुधार का वादा करता है, लेकिन अभी तक का अनुभव यही कहता है कि स्थितियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं हुआ है। इसका परिणाम यह है कि अब लोगों में निराशा घर करने लगी है।

वे मुश्किल से ही अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं। यह समझा जाना चाहिए कि न्यायिक तंत्र में सुधार की बातें करने मात्र से ऐसा होने वाला नहीं है। न्यायपालिका के प्रति लोगों की आस्था डिगे, इसके पहले न्यायिक तंत्र में सुधार के ठोस कदम उठाने होंगे। ऐसा इसलिए भी करना होगा, क्योंकि किसी देश का विकास बहुत कुछ उसकी सुगम न्यायप्रणाली पर निर्भर करता है। जिस देश में समय पर न्याय नहीं मिलता, वहां केवल विवाद ही नहीं बढ़ते, बल्कि विकास के काम भी बाधित होते हैं और व्यवस्था के प्रति असंतोष उपजता है।

इसके चलते नियम-कानूनों की अवहेलना करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। समस्या केवल न्यायपालिका के स्तर पर ही नहीं, कार्यपालिका के स्तर पर भी है। आखिर यह एक तथ्य है कि सरकारें अपने ही लोगों से मुकदमेबाजी में उलझी हुई हैं। अच्छा हो कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलकर समस्या का समाधान करने के लिए आगे आएं। इसमें देरी स्वीकार्य नहीं, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है।

अभियान

कामाख्या बीज की रहस्य-ज्योति

असम की घनी पहाड़ियों में एक ऐसा स्थान है, जहां हवा में भी एक अनदेखा कंपन महसूस होता है। मानो हर झोंका कोई प्राचीन कथा कह रहा हो, हर बादल अपने भीतर कोई पुरानी रहस्यमयी गूँज समेटे हो। नीलाचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या का मंदिर संसार के उन विरले स्थानों में से एक है, जहाँ देवी के स्वरूप में केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि तंत्र की पूर्णता, सिद्धियों का चक्र, और दिव्य ऊर्जाओं का महासमुद्र साकार रूप में विद्यमान है। कहा जाता है कि यहां प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता—चाहे वह धन का याचक हो, चाहे प्रेम का साधक, चाहे सिद्धि का अन्वेषक या चाहे आत्मा की मुक्ति खोजने वाला साधक।

सदियों पहले तांत्रिक गुरुओं ने यहां वह बीज खोजा, जो देवियों की प्रचंड शक्ति को सूक्ष्मतम बिंदु में समेटता है—बीज मंत्र। यह बीज मंत्र ध्वनि नहीं, ऊर्जा है; शब्द नहीं, कंपन है; जप नहीं, जागरण है। यही वह मंत्र है जिससे संसार की दिव्य स्त्री-शक्ति जागृत होती हैः

॥ क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः ॥

इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि यह केवल एक स्तुति नहीं बल्कि एक चाबी है—ऐसी चाबी जो उस द्वार को खोलती है जिसके पीछे मनुष्य की सुप्त इच्छाएँ, सोई हुई सिद्धियाँ, और दबी हुई संभावनाएँ छिपी रहती हैं। इस मंत्र का जाप करने वाला साधक धीरे-धीरे अपने भीतर ऐसे परिवर्तन देखता है जिन्हें शब्दों में बाँध पाना कठिन है।

प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि यह मंत्र तब सबसे अधिक प्रभावी होता है जब साधक पूर्ण शुद्धता से इसका जाप करे। प्रातःकाल का समय इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि उस समय पृथ्वी की ऊर्जा सबसे शांत, सबसे पवित्र और सबसे ग्रहणशील होती है। साधक जब शुद्ध होकर, बिना लहसुन-प्याज़ या भारी भोजन के, शांत चित्त के साथ बैठता है और रुद्राक्ष की 108 दानों वाली माला हाथ में लेकर एकाग्र भाव से इस मंत्र का उच्चारण करता है, तब उसके चारों ओर अदृश्य ऊर्जा का एक मंडल बनने लगता है। मानो स्वयं देवी कामाख्या अपने आभामंडल से साधक को धीरे-धीरे ढँक लेती हैं। मन का हर विकार, हर व्याकुलता, हर भ्रम उस प्रकाश में पिघलने लगता है।

जप के समय साधक यदि फल, मेवे या मिठाई का भोग लगाता है, तो वह देवी की कृपा को और आकर्षित करता है। कहा गया है कि भोग के पीछे देवी का उद्देश्य कुछ खाना नहीं, बल्कि यह देखना है कि साधक ने अपने मन में श्रद्धा कितनी गहराई से स्थापित की है। जब जप समाप्त हो जाता है और साधक उसी भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, तब उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर उतर रही हो—एक हल्की सी गर्माहट, एक स्थिरता, एक नई ऊर्जा।

यदि कोई इस मंत्र का 41 दिनों तक निरंतर जाप करता है, तो यह साधना एक नई परत खोलती है। साधक के जीवन में ऐसा परिवर्तन आने लगता है जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाता—पर अनुभव करता है। उसका आकर्षण बढ़ने लगता है, लोग उसकी ओर खिंचने लगते हैं, उसकी बातें प्रभावकारी हो जाती हैं, उसका व्यक्तित्व चुंबकीय होने लगता है। वह जहां जाता है, वहां उसकी उपस्थिति सहजता से लोगों का ध्यान खींच लेती है। प्रेम जीवन में बाधाएँ हटने लगती हैं और साथी के बीच सौहार्द बढ़ता है।

इसके साथ-साथ साधक के भीतर रचनात्मकता का एक स्रोत खुलने लगता है। उसके विचार अधिक स्पष्ट, अधिक तेज़, अधिक प्रभावी होने लगते हैं। जिन लक्ष्यों तक पहुँचने में उसे वर्ष लगते, अब वही लक्ष्य उसके कुछ ही महीनों की कोशिश में पूरे होने लगते हैं। उसकी उत्पादकता बढ़ती है, उसका आत्मविश्वास प्रचंड शक्ति की तरह जाग उठता है, और वह जीवन की चुनौतियों को एक योद्धा की तरह लेने लगता है।

तांत्रिक ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि यह बीज मंत्र साधक को मां कामाख्या के तांत्रिक स्वरूप से जोड़ता है। साधक चाहे तंत्र का अभ्यास न भी करता हो, परंतु यह मंत्र उसे ऊर्जा के उच्च स्तरों तक पहुँचा देता है। उसके जीवन से बाधाएँ हटने लगती हैं, मार्ग सरल होने लगते हैं, और उसकी इच्छाओं का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि 41 दिनों के जप के बाद उनकी सबसे कठिन मनोकामनाएँ भी पूरी होने लगीं।

कहानी-सा लगता यह सब वास्तविक जीवन में तब घटता है जब साधना सच्ची होती है, भावना निर्मल होती है, और मंत्र का जप उस श्रद्धा से किया जाता है जैसे कोई दीपक अंधकार को चीरने के लिए स्वयं को अर्पित करता है। जो भी व्यक्ति इस मंत्र का आह्वान करता है, वह केवल देवी को नहीं बुलाता, वह अपने भीतर छिपी उस समग्र शक्ति को जागृत करता है जिससे धन, सौभाग्य, प्रेम, आकर्षण, रचनात्मकता और सिद्धि स्वतः उसके जीवन में प्रवाहित होने लगती है। मां कामाख्या का बीज मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसा सूक्ष्म द्वार है जो साधक को उसके वास्तविक सामर्थ्य तक पहुँचाता है। यदि कोई साधक सच्चे मन से बैठकर इस मंत्र का जाप करता है, तो वह धीरे-धीरे महसूस करेगा कि उसकी इच्छाएँ अब हवा में खो जाने वाली आवाज़ नहीं हैं। अब वे ऊर्जा बनकर उसकी ओर लौटती हैं, उसको मार्ग देती हैं, और अंततः उसे वही दे जाती हैं जिसकी उसे सदियों से तलाश होती है—मां कामाख्या का आशीर्वाद।

यह मंत्र साधक के भीतर वह प्रकाश जलाता है जो केवल धन ही नहीं देता, बल्कि वह शक्ति देता है जिससे मनुष्य मनोकामनाओं का सृजनकर्ता बन जाता है। यही कामाख्या बीज की रहस्य-ज्योति है—एक ऐसी ज्योति जो साधक को भीतर से बदल देती है और उसके जीवन को नई दिशा देती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

करमसद से प्रारंभ हुई 'सरदार@150' राष्ट्रीय एकता पदयात्रा 11 दिनों के परिभ्रमण के बाद एकता नगर में समाप्त हुई

एक और अखंड भारत के निर्माण में सरदार साहब का योगदान पीढ़ियों तक अमर रहेगा : उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन

▶▶ उपराष्ट्रपति ने युवाओं से 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत' की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया

▶▶ बारडोली सत्याग्रह ने सरदार साहब को देश भर में मजबूत और कद्दावर जननेता के रूप में स्थापित किया : राज्यपाल आचार्य देवव्रत

▶▶ प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर देश को एक और अखंड करने के संकल्प को साकार किया है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▶▶ 'सरदार@150' राष्ट्रीय एकता पदयात्रा सच्चे अर्थ में 'विचार की यात्रा' बनी : केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री डॉ. मनसुखभाई मांडविया

▶▶ उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में करमसद से एकता नगर तक चले यूनिटी मार्च का समापन समारोह आयोजित

▶▶ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, केंद्रीय मंत्री श्री मनसुखभाई मांडविया सहित मंत्रियों की विशेष उपस्थिति

उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन :-

▶▶ एकता पदयात्रा भारत की अमर आत्मा का उत्सव, जिसमें एकता, कर्तव्य और राष्ट्र निर्माण की भावना का समन्वय हुआ

▶▶ देश की 65 फीसदी आबादी युवा : 'यूथ पावर' देश की ऊर्जा, प्रतिभा और आकांक्षाओं का अद्वितीय स्रोत

▶▶ एकता पदयात्रा देश के जन और मन को जोड़ने का माध्यम बनी

(जीएनएस)। गांधीनगर : लौह पुरुष, देश के प्रथम गृह मंत्री, भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें स्मरणांजलि देने के लिए करमसद से शुरू हुई 'सरदार@150' राष्ट्रीय एकता पदयात्रा 11 दिनों के परिभ्रमण के बाद शनिवार को एकता नगर स्थित सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' परिसर में समाप्त हुई। एकता पदयात्रा के समापन समारोह में उपस्थित उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने इस पदयात्रा को भारत की अमर आत्मा का उत्सव करार दिया। उन्होंने गर्व से कहा कि एकता पदयात्रा देश के जन एवं मन को जोड़ने का माध्यम बनी है, जिसमें एकता, कर्तव्य और राष्ट्र निर्माण की भावना का समन्वय देखने को मिला।

उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि सरदार पटेल हमारे श्रेष्ठ राष्ट्रीय नायक थे, जिन्होंने कुशल नेतृत्व प्रदान कर 560 से अधिक रियासतों को एकीकृत किया। एक और अखंड भारत के निर्माण में सरदार साहब का योगदान पीढ़ियों तक अमर रहेगा। उन्होंने गौरव से कहा कि देश भर में 1300 से अधिक पदयात्राओं में 14 लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी यह सिद्ध करती है कि सरदार पटेल द्वारा प्रज्वलित की गई एकता की ज्योति आज भी जल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरदार साहब से जुड़ी इस पदयात्रा ने पूरे देश में एकता, भाईचारे और एक भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत का संदेश फैलाया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार साहब ने अपने सादगीभरे व्यक्तित्व से दुनिया को संदेश दिया था कि "एग्रीकल्चर इज अवर कल्चर" यानी कृषि ही हमारी संस्कृति का मूल है, और यही हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोकर भारत को एक, अखंड और मजबूत बनाया।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात दुनिया को अहिंसा और सत्य का मार्ग बताने वाले महात्मा गांधी जी, देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल और विकास को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जन्मभूमि है। देश के किसी भी कोने में 'केम छो?' कहने पर, प्रत्युत्तर में 'मजा मां!' सुनने को मिलता है, यह भावना गुजरात की प्रगतिशील विचारधारा और प्रधानमंत्री के लोकप्रिय नेतृत्व का प्रतिबिंब है।

श्री राधाकृष्णन ने कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में आर्थिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति तथा रणनीति जैसे अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। नारी शक्ति वंदन कानून ने स्त्री सशक्तिकरण से आगे बढ़कर वुमन-लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास का युग शुरू किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में चार नई श्रम संहिताएं (लेबर कोड्स) लागू की हैं, जो न्यायपूर्ण, सर्वसमावेशी और प्रगतिशील भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत आधार देती हैं। ये श्रम संहिताएं देश के श्रमिक वर्ग के लिए समानता और सम्मान का पथ प्रशस्त करेंगी।

उन्होंने कहा कि सरदार पटेल जी का मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में तेजी से साकार हो रहा है। सरदार साहब के आदर्श विचारों की विरासत आज आत्मनिर्भर भारत और 'विकसित भारत@2047' के संकल्प में नजर आती है।

उपराष्ट्रपति ने युवाओं को ड्रग्स के शिकंजे में कभी न फंसने की सीख देते हुए कहा कि युवा शक्ति देश का भविष्य है। देश की 65 फीसदी आबादी युवा है और 'यूथ पावर' देश की ऊर्जा, प्रतिभा और आकांक्षाओं का अद्वितीय स्रोत है, ऐसे में उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे खेल, सामाजिक दायित्व और संस्कारपूर्ण व्यवहार के माध्यम से बदलते समय में अपनी क्षमताओं को विकास की दिशा में मोड़ें।

उपराष्ट्रपति ने युवाओं को 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत' की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि बारडोली सत्याग्रह ने सरदार साहब को देश भर में मजबूत और कद्दावर जननेता के रूप में स्थापित किया। वल्लभभाई पटेल ने अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण कर वृद्धि (लगान वृद्धि) के खिलाफ आंदोलन का आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उस समय वे एक सफल वकील थे और आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने देश सेवा के लिए अपनी वकालत छोड़ दी।

उन्होंने कहा कि सरदार पटेल जी ने बारडोली के गांव-गांव में घूमकर किसानों को इकट्ठा किया, उनमें आत्मविश्वास जगाया और उन्हें एकता के सूत्र में बांधने का भगीरथ कार्य किया था। ऐसे मुश्किल वक्त में सरदार पटेल ने सफल सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया। किसानों की इस जीत और उनके नेतृत्व के कारण ही वल्लभभाई पटेल को 'सरदार' का सम्मानित नाम मिला।

राज्यपाल ने कहा कि एकता नगर में सरदार साहब की दुनिया की सबसे विराट प्रतिमा का निर्माण करवाकर उन्हें देश की एकता और अखंडता का प्रतीक बनाया है। देश भर में आयोजित पदयात्राएं सरदार साहब के जीवन आदर्शों और सत्कार्यों से नई ऊर्जा प्राप्त करेंगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के समारोह का वर्ष पूरे देश में राष्ट्र गौरव को उजागर करने वाला एक ऐतिहासिक वर्ष बन गया है। यह वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती तथा सरदार साहब की विचारधारा के वैश्विक प्रचार-प्रसार का प्रेरणास्रोत बन रहा है।

उन्होंने देश की एकता के शिल्पी सरदार साहब को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत एक सक्षम राष्ट्र के रूप में खड़ा है, यह सरदार पटेल की राजनीति, हिम्मत और मजबूत इच्छाशक्ति का नतीजा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि डॉ. बाबासाहब अंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान हमारे राष्ट्र के बंधुत्व के संकल्प का प्रतीक है। 26 नवंबर को संविधान अंगीकार दिवस से शुरू हुए इस राष्ट्रीय यूनिटी मार्च का डॉ. बाबासाहब की पुण्य तिथि-परिनिर्वाण दिवस पर पूर्ण होना अपने आप में एक अनोखा और प्रेरणादायी संदेश देता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे 'एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान' को स्थापित करने के संकल्प को जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर साकार किया है। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गुजरात के केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि युवा शक्ति विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव है। इस यूनिटी मार्च में जुड़े युवाओं में अदम्य ऊर्जा और प्रेरणा देखने को मिली है। बिना थके, लगातार चलते रहने वाले युवाओं की इस यात्रा को 'सकारात्मक कदम' भी कहा जा सकता है। यात्रा के दौरान सरदार वंदना और राष्ट्रभक्ति के रंगों के साथ-साथ स्वच्छता, एक पेड़ मां के नाम जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी द्वारा दिए गए आयामों को युवा शक्ति ने हृदय से चरितार्थ किया है। एकता का, समरसता का और सामूहिक विकास का भाव हर क्षण दिखाई दिया है।

समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि हम सभी को सरदार साहब के 'राष्ट्र प्रथम' के सिद्धांत को हृदय में रखकर देश के विकास के पथ पर अडिग रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि 'विकसित भारत@2047' के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता, कार्यशीलता और एकता की भावना के साथ आगे बढ़ना मौजूदा दौर की मांग है।

केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री डॉ. मनसुखभाई मांडविया ने कहा कि यह पदयात्रा सरदार साहब के पैतृक गांव करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (एकता नगर) तक 150 किलोमीटर की इस पदयात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने स्वयं चार दिनों तक भाग लिया। उन्होंने कहा कि 150 स्थायी पदयात्रियों के साथ देश भर से असंख्य युवा और महिलाएं तथा गुजरात के कोने-कोने से हजारों युवा अपनी क्षमता के अनुसार एक, दो या तीन दिनों के लिए इस यात्रा में शामिल हुए, जिसके कारण यह पदयात्रा सच्चे अर्थ में 'विचार की यात्रा' बन गई है।

श्री मनसुखभाई ने यात्रा के दौरान जनता के उत्साहपूर्ण समर्थन का उल्लेख करते हुए कहा कि पदयात्रा जहां से भी गुजरी, वहां जनता ने जोश-खरोश के साथ स्वागत किया। बड़ी संख्या में लोग पदयात्रा में स्वतःस्फूर्त शामिल हुए हैं। किसानों ने भी इस यात्रा में अनोखा योगदान दिया है। उन्होंने अपने खेतों में पके केले और अमरूद आदि पदयात्रियों को खिलाकर उनका स्वागत किया। इस पदयात्रा के दौरान किसानों ने रास्ते में प्राकृतिक खेती का प्रदर्शन कर 'आत्मनिर्भर भारत' का संदेश फैलाया। यह पदयात्रा राष्ट्र को एकता यात्रा के रूप में संदेश दे रही है और प्रधानमंत्री के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार कर रही है।

इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने स्वदेशी अपनाकर 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण की शपथ ली।

उल्लेखनीय है कि 'सरदार@150' राष्ट्रीय एकता पदयात्रा 26 नवंबर को सरदार साहब के जन्म स्थान करमसद से शुरू हुई थी। 11 दिनों तक चली यह यात्रा आणंद के अलावा वडोदरा, नर्मदा जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिभ्रमण करने के बाद 6 दिसंबर को नर्मदा जिले के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंची। राष्ट्रीय यूनिटी मार्च में जुड़े ऊर्जावान युवाओं, महानुभावों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्था के लोगों, स्वयंसेवकों और स्थानीय नागरिकों ने आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए जन-जन तक एकता का संदेश पहुंचाया।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, स्वराज आश्रम-बारडोली की ट्रस्टी निरंजनाबेन कलार्थी, सांसद श्री मनसुखभाई वसावा और जशुभाई राठवा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री भीमसिंहभाई तड़वी, विधायक डॉ. दर्शनाबेन देशमुख सहित जिला प्रशासन के अधिकारी, पदयात्री और बड़ी संख्या में सरदार प्रेमी नागरिक उपस्थित रहे।

सप्ताह के दौरान सोना वायदा में 2411 रुपये और चांदी वायदा में 12151 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा में 93 रुपये की तेजी

(जीएनएस)। कॉटन, मेंथा तेल में नरमी का माहौलः इलायची में सुधारः कमोडिटी वायदाओं में 426235.42 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 2174156.04 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में 335588.19 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 31010 पॉइंट के स्तर पर

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 28 नवंबर से 4 दिसंबर के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 2600460.97 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 426235.42 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 2174156.04 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 31010 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में सप्ताह का कुल प्रीमियम टर्नओवर 31032.05 करोड़ रुपये का हुआ।

आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 335588.19 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 128352 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 131400 रुपये के उच्च और 127891 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 127667 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 2411 रुपये या 1.89 फीसदी की तेजी के संग 130078 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा सप्ताह के अंत में 1985 रुपये या 1.94 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 104197 रुपये प्रति 8 ग्राम पर बंद हुआ। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 242 रुपये या 1.89 फीसदी की तेजी के संग 13048 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। सोना-मिनी जनवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 126860 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 130170 रुपये के उच्च और 126860 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 2200 रुपये या 1.74 फीसदी की मजबूती के साथ सप्ताह के अंत में 128894 रुपये प्रति 10 ग्राम बंद हुआ। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सप्ताह के आरंभ में 127105 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 130350 रुपये के उच्च और 127105 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 126904 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 2288 रुपये या 1.8 फीसदी की बढ़त के साथ 129192 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 167190 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 184743 रुपये और नीचे में 166980 रुपये पर पहुंचकर, 165987 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 12151 रुपये या 7.32 फीसदी बढ़कर 178138 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा सप्ताह के अंत में चांदी-मिनी फरवरी वायदा 12266 रुपये या 7.36 फीसदी की तेजी के संग 178937 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 12328 रुपये या 7.4 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट सप्ताह के अंत में 178943 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ।

मेटल वर्ग में 25221.11 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा सप्ताह के अंत में 52.9 रुपये या 5.18 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1073.6 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 9.15 रुपये या 3.06 फीसदी की मजबूती के साथ सप्ताह के अंत में 308.25 रुपये प्रति किलो बंद हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 7.8 रुपये या 2.88 फीसदी बढ़कर 278.25 रुपये प्रति किलो के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 1.3 रुपये या 0.72 फीसदी बढ़कर सप्ताह के अंत में 183.05 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 65410.44 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल दिसंबर वायदा सप्ताह के आरंभ में 5281 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 5398 रुपये और नीचे में 5258 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 93 रुपये या 1.76 फीसदी की तेजी के संग 5383 रुपये प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी दिसंबर वायदा 92 रुपये या 1.74 फीसदी की बढ़त के साथ 5381 रुपये प्रति बैरल के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा सप्ताह के आरंभ में 415.5 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 455.6 रुपये और नीचे में 410.1 रुपये पर पहुंचकर, 413.1 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 34.3 रुपये या 8.3 फीसदी की तेजी के संग 447.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर बंद हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 34.5 रुपये या 8.35 फीसदी की मजबूती के साथ 447.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा सप्ताह के आरंभ में 909 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 6.3 रुपये या 0.69 फीसदी औंधकर 903.2 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। कॉटन दिसंबर वायदा सप्ताह के अंत में प्रति गांठ 20 रुपये या 0.08 फीसदी घटकर 25130 रुपये पर बंद हुआ। इलायची दिसंबर वायदा सप्ताह के आरंभ में 2685 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में सप्ताह के अंत में यह वायदा 29 रुपये या 1.09 फीसदी की बढ़त के साथ 2700 रुपये पर बंद हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 156847.73 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 178740.46 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 20087.80 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 1579.47 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 291.50 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 3258.11 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 6847.33 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 58455.07 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 10.54 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 1.00 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सप्ताह के अंत में सोना के वायदाओं में 13025 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 44282 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 9121 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 150163 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 14072 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 14599 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 33063 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 74968 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 13203 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 24555 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा सप्ताह के आरंभ में 30197 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 31551 के उच्च और 30010 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 997 पॉइंट बढ़कर 31010 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।

'गेट्स फाउंडेशन' ने गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम को महिलाओं के भारी मासिक धर्म रक्तस्राव से संबंधित रिसर्च के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी

▶▶ यह रिसर्च महिलाओं को पीरियड्स के दौरान होने वाली तकलीफों को दूर करने में सहायक होगी

▶▶ कम सुविधा वाले इलाकों में भारी मासिक धर्म रक्तस्राव (एचएमबी) की वजह का पता लगाने के लिए होगा आधुनिक डायग्नोस्टिक्स और एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग

▶▶ एचएमबी की समस्या के निवारण और इस विषय में जागरूकता फैलाने के लिए महिलाओं को करेगा आमंत्रित जीबीयू

(जीएनएस)। गांधीनगर : गेट्स फाउंडेशन राज्य सरकार की ओर से संचालित गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी (जीबीयू) की रिसर्च टीम को महिलाओं को पीरियड्स यानी माहवारी के दौरान होने वाले भारी रक्तस्राव पर रिसर्च करने के लिए करीब 1.3 करोड़ रुपए की सहायता देगा। गेट्स फाउंडेशन की फंडिंग के अंतर्गत जीबीयू की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रोहिणी नायर के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम 'हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग-एचएमबी' यानी महिलाओं के पीरियड्स के दौरान होने वाले भारी रक्तस्राव के लिए यानी आरएनए-आधारित यानी राईबोन्यूक्लिक एसिड पर आधारित डायग्नोस्टिक एवं उपचार के लिए संसाधन विकसित करने के लिए कार्य करेगी। ये संसाधन सस्ते, स्केलेबल यानी विस्तार करने में सक्षम और कम आक्रामक होंगे। विशेषकर, दूरदराज के इलाकों में महिलाओं के लिए जल्दी निदान, व्यक्तिगत उपचार और मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट में सुधार लाने के उद्देश्य के साथ इस प्रोजेक्ट को 'गेट्स फाउंडेशन ग्रैंड चैलेंजेस सपोर्ट' के तहत स्वीकृत किया गया है। गेट्स फाउंडेशन ने इसके लिए लगभग 1.3 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की है।

डॉ. रोहिणी नायर ने इस विषय में बताया कि गेट्स फाउंडेशन ने फरवरी, 2025 में 'ग्रैंड चैलेंजेस' फंडिंग कॉल शुरू किया था, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर, लेकिन अक्सर उपेक्षा का शिकार रहने वाली समस्या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के निवारण के लिए अभिनव दृष्टिकोण आमंत्रित किए गए थे। फाउंडेशन मूल्यांकन के लिए दो चरणों की प्रक्रिया का पालन करता है, जिसकी शुरुआत कंसेप्ट नोट या लेटर ऑफ इंक्वायरी (एलओआई) से होती है। इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से संपूर्ण प्रपोजल मंगाया जाता है, ताकि वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं और वैज्ञानिक सावधानी या सटीकता बनी रहे। भारी मासिक धर्म रक्तस्राव की समस्या के निवारण और इस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए जीबीयू की ओर से महिलाओं को भी आमंत्रित किया जाएगा, ताकि यह अन्य महिलाओं के लिए मददगार साबित हो सके। यह रिसर्च-स्टडी अहमदाबाद की इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर (आईकेडीआरसी) के ऑब्स्टेट्रिक्स (प्रसूति रोग) और गायनेकोलॉजी (स्त्री रोग) विभाग की डीन एवं हेड डॉ. रोहिना अग्रवाल के सहयोग से की जाएगी।

रिसर्च के अंतर्गत डॉ. अग्रवाल मरीजों की पहचान और चिकित्सा मूल्यांकन में मुख्य भूमिका निभाएंगी, जबकि डॉ. नायर की लेबोरेटरी महिलाओं के स्वास्थ्य रिसर्च पर ध्यान केंद्रित करेंगी। वे, विशेषकर गर्भ धारण करने में बार-बार होने वाली असफलता (RIF - Repeated Implantation Failure) और एंडोमेट्रिओसिस पर एचएमबी के लिए आरएनए-आधारित किफायती और न्यूनतम आक्रामक संसाधन विकसित करने पर सक्रिय रूप से कार्य करेंगी।

डॉ. नायर ने आगे कहा कि आज भारी माहवारी रक्तस्राव (एचएमबी) से दुनिया भर की लाखों महिलाएं प्रभावित हैं। इसके चलते एनीमिया, कार्यक्षमता में कमी, लंबे समय तक थकान महसूस करना और जीवन की गुणवत्ता कमजोर पड़ने जैसी समस्याएं खड़ी होती हैं। इसका प्रभाव उन इलाकों में अधिक गंभीर है, जहां समय पर डायग्नोसिस और प्रभावी उपचार की कम सुविधाएं हैं। यह प्रोजेक्ट हार्मोनल इन्ट्रा-यूरेटाइन डिवाइस जैसे उपचार की स्वीकार्यता और पहुंच बढ़ाने के रास्तों की भी खोज करेगा। एचएमबी के व्यापक प्रसार के बावजूद, अभी इसके पीछे के जैविक कारणों के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह केवल वृद्ध महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि युवा पीढ़ी में भी देखने को मिलता है। हालांकि, हमारे सामाजिक परिवेश के कारण महिलाएं खुलकर बात नहीं कर पातीं और आम तौर पर दर्दनिवारण दवाइयां लेकर अपना काम चलाती हैं।

इस समस्या के बारे में अधिक जानकारी देते हुए डॉ. नायर ने कहा कि एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग यानी असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव, जिसका एचएमबी एक विषय है, वह विभिन्न कारकों के कारण होता है। जिनमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज जैसे कि पोलिप्स, एडिनोमायोसिस, फाइब्रोइड्स और मैलिग्नेंसी-कैंसर शामिल हैं। वहीं, नॉन-स्ट्रक्चरल कारकों में ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी रक्तस्राव विकार, ओव्यूलेटरी और एंडोमेट्रियल डिसफंक्शन का सामवेश होता है।

इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सिंगल-सेल आरएन सिक्वेंसिंग का उपयोग करके एचएमबी के सेलुलर और मॉलिक्युलर कारकों को मैप करना है, जिससे कि एंडोमेट्रियल माइक्रोएन्वायर्नमेंट का व्यापक डेटा संग्रह तैयार किया जा सके। उम्मीद है कि इस कार्य से मिलने वाली जानकारी असामान्य मासिक रक्तस्राव से जुड़े मुख्य पाथ-वे यानी मार्ग और बायोमार्कर्स की पहचान करेगी।

गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के डीन रिसर्च प्रो. सुधीर प्रताप सिंह ने कहा कि जीबीयू इस उपलब्धि को वैश्विक महिला स्वास्थ्य रिसर्च में भारत के योगदान के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानता है और प्रभावशाली एवं विज्ञान-आधारित रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। एचएमबी पर रिसर्च प्रोजेक्ट का मुख्य फोकस एरिया एचएमबी यानी भारी मासिक रक्तस्राव की फंडामेंटल बायोलॉजी की समझ को आगे बढ़ाना और कम सुविधाओं वाले इलाकों में महिलाओं में इस रोग के फैलाव, प्रभाव और स्त्री रोग स्वास्थ्य तथा जीवन की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना है। इसके अलावा, ध्यान केद्रित करने के अन्य क्षेत्रों में, एचएमबी की जांच के लिए संशोधित पद्धतियां विकसित करना और उन्हें प्रमाणित करना तथा स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च प्रोटोकॉल स्थापित करना और कम सुविधाओं वाले इलाकों में एचएमबी के कारणों की पहचान करने के लिए अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक्स तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के साथ-साथ उपचार की प्रभावशीलता, स्वीकार्यता और उपचार तक पहुंच बढ़ाने के रास्तों का मूल्यांकन करना शामिल हैं।

पश्चिम रेलवे चलायेगी साबरमती से दिल्ली और दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच स्पेशल ट्रेनें

(जीएनएस)। यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाए रखने के लिए पश्चिम रेलवे पूर्णतः प्रतिबद्ध है। यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा ट्रेन ऑन डिमांड (TOD) के अंतर्गत साबरमती-दिल्ली जंक्शन और साबरमती-दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः

1. ट्रेन संख्या 09497/09498 साबरमती-दिल्ली जं. सुपरफास्ट स्पेशल (4 फेरे)

ट्रेन संख्या 09497 साबरमती-दिल्ली स्पेशल 7 और 9 दिसंबर 2025 को साबरमती से 22.55 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 15.15 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09498 दिल्ली–साबरमती स्पेशल 8 और 10 दिसंबर 2025 को दिल्ली जं. से 21.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 12.20 बजे साबरमती पहुंचेगी। मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़ जं.,अजमेर, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, गुडगाँव एवं दिल्ली केंट स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी 3-टियर श्रेणी के कोच रहेंगे।

2. ट्रेन संख्या 04061/4062 साबरमती-दिल्ली सराय रोहिल्ला-साबरमती स्पेशल (2 फेरे)

ट्रेन संख्या 04061 साबरमती-दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल 07 दिसंबर 2025 को साबरमती से प्रातः 05.30 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन रात्री 23.00 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी। इसी तरह से ट्रेन संख्या 04062 दिल्ली सराय रोहिल्ला-साबरमती स्पेशल 06 दिसंबर 2025 को दिल्ली सराय रोहिल्ला से 08.10 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 07 दिसंबर 2025 को 00.30 बजे साबरमती पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में पालनपुर, आबूरोड, फालना, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, गुडगाँव एवं दिल्ली केंट स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन एसी 2 टियर एवं एसी 3-टियर श्रेणी के आरक्षित कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09497 एवं 04061 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू है। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

कच्छ के भुजोडी गांव के 46 बुनकरों ने हासिल किया राष्ट्रीय सम्मान

VGRC में कच्छ की विरासत को नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध

▸▸ राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भुजोडी के बुनकर आज भी प्राचीन हस्तकरघा कला को आधुनिक दौर में जीवंत बनाए हुए हैं

▸▸ "कला ही जीवन है": VGRC के माध्यम से भुजोडी के बुनकरों को मिलेगा वैश्विक सफलता का मार्ग

(जीएनएस)। गांधीनगर : कच्छ का भुजोडी गाँव पारंपरिक कारीगरी का एक जीवंत और सशक्त केंद्र है। यह गाँव अपने 46 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्पियों के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। इस समृद्ध शिल्प विरासत में 6 संत कबीर पुरस्कार प्राप्तकर्ता, 20 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, 1 शिल्प गुरु, 4 कला-निधि पुरस्कारधारी और हैंडलूम–हस्तकला क्षेत्र में विभिन्न राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले बुनकर भी इसमें शामिल हैं। भुजोड़ी के वांकर समुदाय के कुशल बुनकर गुजरात की समृद्ध, राजसी युग से चली आ रही वस्त्र परंपरा का गौरवपूर्ण उदाहरण हैं, जो आज भी आधुनिक युग में अपने प्राचीन कौशल की चमक बरकरार रखे हुए हैं। भुजोडी के कारीगर नानजी भीमजीभाई खारेत बताते हैं कि उन्हें और पूरे गाँव को प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनियों में वीवर्स सर्विस सेंटर विभाग से भरपूर सहयोग मिला है। भुजोडी के कारीगर फैबइन्डिया, जयपोर और गरवी गुजरात जैसी प्रतिष्ठित ब्रांड्स के साथ भी काम करते हैं।

भुजोडी विश्वभर में अपने हैंडलूम बुनाई के लिए जाना जाता है, जहाँ विश्व विख्यात भुजोडी शॉल, पारंपरिक ऊनी रजाइयाँ और कंबल तैयार किए जाते हैं। यहाँ के शिल्पकार जटिल बुनाई तकनीकों, पारंपरिक डिज़ाइनों और प्राकृतिक, समय-परखी रंगों का इस्तेमाल कर गुजरात के इतिहास की असल बनावट और सांस्कृतिक कथा को जीवित रखते हैं। यह सिर्फ कारीगरी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण का महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसे इन कारीगरों ने अपनी पीढ़ियों की मेहनत और समर्पण से जीवित रखा है।

अब इस विरासत के संरक्षण को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलने जा रहा है। जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में राजकोट में आयोजित होने वाले दूसरे वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेन्स (VGRC) और वाइब्रेंट गुजरात रीजनल एग्ज़िबिशन (VGRE) में भुजोडी के ये शिल्पी विशेष रूप से भाग लेने जा रहे हैं। यह सहभागिता आर्थिक और नीतिगत, दोनों स्तरों पर बड़े लाभ का आधार बनेगी। यह क्षेत्रीय सम्मेलन कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति विशेषकर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

इस कार्यक्रम में एक विशेष क्राफ्ट्स विलेज बनाया जाएगा जहाँ ये कारीगर अपने पुरस्कार-विजेता शिल्प का प्रदर्शन कर सकेंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण रिवर्स बायर–सेलर मीट (RBSM) भी आयोजित होगी जो इन MSMEs को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से सीधे जोड़ेगी और नए निर्यात बाज़ारों के द्वार खोलेगी।

इसके अलावा, सम्मेलन का उद्यमी मेला कारीगरों को तात्कालिक व्यावसायिक सहयोग, आर्थिक सहायता, वित्तीय लिंकेज और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करेगा जिससे समुदाय की उद्यमशीलता क्षमता और भी मजबूत होगी। पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान यह सुनिश्चित करेगा कि भुजोडी के ये पारंपरिक शिल्पकार अपनी कला-संरक्षण की मेहनत का स्थायी आर्थिक लाभ उठा सकें।

राजकोट का यह VGRC आयोजन भुजोडी के शिल्पियों के लिए अपने अनुभव, पुरस्कार और वैश्विक पहचान को दीर्घकालिक व्यापारिक सफलता में बदलने का एक ऐतिहासिक अवसर है। यह वह महत्वपूर्ण मोड़ है, जहाँ भुजोडी की कला विरासत को वैश्विक मंच पर निरंतर फलने–फूलने के लिए आवश्यक निवेश और पहचान मिलने की उम्मीद है।

भावनगर मंडल में री-ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन हेतु निवारण कैंप का सफल आयोजन

(जीएनएस)। री-ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों के मार्गदर्शन एवं त्वरित समाधान के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा आज परिवारिक पेंशन निवारण कैंप का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। मंडल प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों, पेंशनरों एवं उनके आश्रितों को पारदर्शी, सुगम एवं समयबद्ध सेवाएँ उपलब्ध कराना है। इस कैंप में भावनगर मंडल के विभिन्न स्टेशनों से लगभग 200 से अधिक आवेदक सम्मिलित हुए। स्थापना एवं लेखा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सभी आवेदकों को रेलवे के निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, सामान्य त्रुटियों तथा अनावश्यक विलंब से बचने के उपायों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस अवसर पर पेंशनर एसोसिएशन, भावनगर के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन की अध्यक्षता में दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर सहायक कार्मिक अधिकारी श्री वाई. राधेश्याम, सहायक कार्मिक अधिकारी श्री संतोष कुमार वर्मा एवं सहायक मंडल वित्त प्रबंधक श्री संजय सक्सेना उपस्थित रहे, जिन्होंने री-ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन से संबंधित मामलों में आवेदकों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। कैंप के दौरान निपटारा अनुभाग, लेखा विभाग एवं कल्याण अनुभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं, जिनमें परिवारिक पेंशन मामलों का परीक्षण एवं निवारण, नामांकन एवं फैमिली डिक्लेरेशन का सत्यापन, आवश्यक दस्तावेजों की जाँच, पात्रता संबंधी जानकारी तथा पेंशन प्रक्रियाओं से जुड़ी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान प्रमुख रूप से शामिल रहा।

विभिन्न स्टेशनों से पधारे आवेदकों एवं उनके परिजनों ने इस पहल को अत्यंत उपयोगी, सहयोगपूर्ण एवं समय बचाने वाला बताया। भावनगर मंडल प्रशासन भविष्य में भी पेंशनरों एवं उनके आश्रितों के कल्याण हेतु ऐसे ही लाभकारी एवं जनोपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा, जिससे सभी लाभार्थियों को रेलवे द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ सरल, सुगम एवं प्रभावी रूप से प्राप्त होती रहें।

इस अवसर पर आवेदकों की सुविधा एवं जानकारी हेतु एक हेल्पलाइन नंबर 9974387220 भी जारी किया गया है, जिस पर री-ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन से संबंधित जानकारी सोमवार से शुक्रवार सायं 15:00 से 18:00 बजे के बीच प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम का संचालन मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक श्री शैलेश कुमार परमार द्वारा किया गया।

सीमाओं पर सुरक्षा को नई धार: देश में पहली बार 3डी तकनीक से बनेंगे सेना के सुपर–मजबूत बंकर

(जीएनएस)। देश की उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में भारतीय सेना ने एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए पहली बार फॉरवर्ड इलाकों में ऑन-साइट 3डी कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का संचालन शुरू कर दिया है। सिक्किम की ऊंची चोटियों से लेकर बर्फीली चौकियों तक, सेना अब ऐसे बेहद कठिन इलाकों में भी कम समय में अत्याधुनिक बंकर और सुरक्षा ढाँचे तैयार कर सकेगी। यह तकनीक 'प्रोजेक्ट प्रबल' के तहत विकसित की गई है, जिसे भारतीय सेना और आईआईटी हैदराबाद ने मिलकर तैयार किया है। पूरी तरह स्वदेशी इस तकनीक ने सीमा निर्माण में एक नया अध्याय खोल दिया है।

सिक्किम सेक्टर में तैनात त्रिशक्ति कोर ने हाल ही में कई अग्रिम पोस्टों पर 3डी प्रिंटेड संरचनाओं का परीक्षण किया, जिनमें भूकंप, भारी बर्फबारी, तेज हवाओं और गोलीबारी जैसे कठिन हालात को ध्यान में रखा गया था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, सभी संरचनाएँ इन परिस्थितियों में बिल्कुल स्थिर और भरोसेमंद पाई गईं। यह सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पारंपरिक निर्माण में जहाँ सप्ताहों से महीनों का समय लगता है, वहीं 3डी प्रिंटिंग तकनीक के जरिए वही काम कुछ घंटों या दिनों में पूरा किया जा सकता है।

भारतीय सेना के अधिकारियों के अनुसार, यह तकनीक भविष्य के युद्धक्षेत्र की मांगों को पूरा करने में निर्णायक साबित होगी। यह न सिर्फ तेजी से निर्माण की सुविधा देती है, बल्कि बुलेट और ब्लास्ट रेसिस्टेंस भी बढ़ाती है। इस तकनीक से तैयार बंकर, पोस्ट और स्टोरेज यूनिट सैनिकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करेंगे और घुसपैठ या गोलाबारी जैसे आपात हालात में तुरंत नई संरचनाएँ खड़ी की जा सकेंगी। यह क्षमता बिजनेस-एज-यूज़ुअल को बदलते हुए सेना को सामरिक बढ़त देने जा रही है। 3डी प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले पोर्टेबल रोबोटिक प्रिंटर में उन्नत रोबोटिक आर्म, मिक्सर, पावर यूनिट और पिस्टन पंप शामिल हैं, जो इसे पहाड़ी इलाकों में भी उपयोगी बनाते हैं। यह पूरी तरह वाहन-पोर्टेबल है और कम समय में किसी भी फॉरवर्ड लोकेशन तक पहुँचकर तुरंत काम शुरू कर सकता है। इस तकनीक से बने ढाँचों के लिए कस्टमाइज्ड डिजाइन तैयार करना भी आसान है, जिससे इलाके की जरूरतों के हिसाब से सुरक्षा संरचनाएँ बनाई जा सकती हैं। सेना ने लाइव बैलिस्टिक ट्रायल के दौरान इसकी मजबूती का परीक्षण किया, जिसमें तकनीक ने सभी मानकों पर सफलता हासिल की। विशेषज्ञों का कहना है कि सीमाओं पर खड़े होने वाले "भविष्य के बंकर" अब हल्के, मजबूत, टिकाऊ और जटिल भूगोल में भी आसानी से स्थापित किए जा सकेंगे। स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग, लागत में कमी और तेजी से निर्माण—ये सभी फायदे इसे युद्धकालीन इंजीनियरिंग के लिए आदर्श बनाते हैं। आने वाले समय में सेना इस तकनीक को और व्यापक स्तर पर अपनाने की तैयारी कर रही है, ताकि सभी संवेदनशील मोर्चों पर आधुनिक सुरक्षा ढांचे विकसित किए जा सकें।

देश के रणनीतिक हितों के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीमाओं पर सुरक्षा की नई परिभाषा गढ़ते हुए भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह आधुनिक तकनीक के जरिये अपने जवानों को हर संभव सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य के संघर्षों में जहां गति और तकनीक निर्णायक होंगी, वहीं भारतीय सेना का यह नवाचार देश की सीमाओं को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और सुदृढ़ बनाएगा।

गोयल ने दीक्षांत समारोह में कहा-"विश्वविद्यालय बनें भारत के भविष्य की प्रयोगशाला, प्रतिभा को दें सबसे बड़ा मंच"

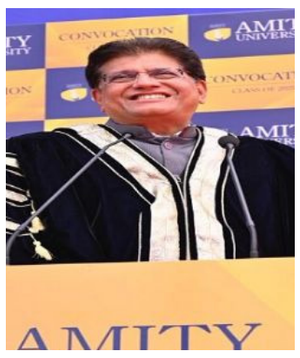

(जीएनएस)। नई दिल्ली। एमिटी विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में शनिवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को एक गहरी और दूरदर्शी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत के विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने वाले संस्थान न हों, बल्कि वे ऐसी प्रयोगशालाएं बनें जहां देश का भविष्य तैयार होता है। जहां छात्रों को अवसर मिले, उनकी प्रतिभा को पहचान मिले और उनकी क्षमता को निखारने के लिए ऐसा वातावरण बनाया जाए, जो उन्हें वैश्विक मंच पर गर्व से खड़ा कर सके।

नोएडा स्थित एमिटी विश्वविद्यालय में आयोजित इस समारोह में इस वर्ष लगभग 29,000 स्नातक छात्रों ने ऑनलाइन और ऑन-कैंपस माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी की। हजारों नव-प्रवर्तक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, कलाकार और स्टार्टअप संस्थापक एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत का जश्न मना रहे थे, और इसी मंच पर गोयल ने कहा कि किसी भी दीक्षांत समारोह की असली चमक छात्रों की उपलब्धियों में होती है—उनमें नहीं जो मंच पर बैठे होते हैं।

गोयल ने एमिटी के छात्रवृत्ति कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास यह सुनिश्चित करते हैं कि आर्थिक बाधाएँ किसी छात्र की प्रतिभा के रास्ते में रुकावट न बनें। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों में लगभग आधी संख्या युवा महिलाओं की है, जो नए भारत की बदलती तस्वीर और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि एमिटी के छात्रों द्वारा अब तक 450 से अधिक पेटेंट हासिल किए जा चुके हैं, जो किसी भी विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है और इसकी नवाचार संस्कृति का मजबूत संकेत भी।

समारोह में गोयल ने यह भी बताया कि संस्थान के 50 संकाय सदस्य रामलिंगम स्वामी फेलो हैं—वे लोग जिन्होंने अपने विशिष्ट अनुभव और ज्ञान से विज्ञान, अनुसंधान और समाज सेवा में योगदान दिया है। उन्होंने इसे एक ऐसी पूँजी बताया जो छात्रों की मार्गदर्शिका बनकर उन्हें सही दिशा देने में मदद करती है।

स्नातक छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्ष—2047 तक का काल—भारत के लिए निर्णायक युग होगा। जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, वह युवा पीढ़ी की ऊर्जा, समर्पण और नवाचार की धार पर ही निर्भर करेगा। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सीमाओं को तोड़ें, परंपरागत सोच से बाहर निकलें और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएँ।

उन्होंने कहा कि देश तभी आगे बढ़ेगा, जब हर युवा यह संकल्प ले कि वह सिर्फ अपने करियर के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए भी काम करेगा। विश्वविद्यालयों की भूमिका है ऐसे युवा तैयार करना—जो न सिर्फ तकनीकी रूप से सक्षम हों, बल्कि मूल्य-आधारित और राष्ट्र-केन्द्रित भी हों।

समारोह तालियों की गड़गड़ाहट, गर्व से भरे चेहरों और सपनों से भरी आँखों के साथ खत्म हुआ, लेकिन पीयूष गोयल का संदेश छात्रों के मन में लंबे समय तक गूंजता रहेगा—"भारत का भविष्य आपके हाथों में है, और विश्वविद्यालय उसका पहला आधार स्तंभ।"

अगले हफ्ते बाजार में आईपीओ का तूफान: 12 ऑफर खुलेंगे, निवेशकों के सामने 14,000 करोड़ का बड़ा मौका

(जीएनएस)। मुंबई। भारतीय शेयर बाजार आने वाले हफ्ते में जबरदस्त हलचल के लिए तैयार है। 8 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 के बीच मेनबोर्ड और एसएमई मिलाकर कुल 12 आईपीओ निवेशकों के लिए खुलने जा रहे हैं। अनुमान है कि इन सार्वजनिक निर्गमों के जरिए लगभग 14,000 करोड़ रुपये बाजार से जुटाए जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा उस बहुप्रतीक्षित आईपीओ की है, जिसका इंतजार महीनों से हो रहा था—आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट का इश्यू, जो 12 दिसंबर को आने वाला है और इसे हाल के वर्षों का सबसे बड़ा वित्तीय आईपीओ माना जा रहा है।

अगले सोमवार से बाजार में आईपीओ की भरमार शुरू होगी। मेनबोर्ड पर कोरोना रेमेडीज़ और वेकफिट इनोवेशंस की एंट्री होने वाली है। कोरोना रेमेडीज़ फार्मा सेक्टर की एक प्रमुख मिड-साइज कंपनी है, जो 655.37 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल पेश कर रही है। कंपनी के शेयर 1,008 से 1,062 रुपये प्रति शेयर की रेंज में उपलब्ध होंगे। दूसरी ओर, वेकफिट इनोवेशंस का 1,288.89 करोड़ रुपये का आईपीओ भी निवेशकों के लिए खास आकर्षण रहेगा। इसका प्राइस बैंड 185 से 195 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जिससे इसकी मांग

को लेकर बाजार में पहले से ही चर्चा तेज है।

एसएमई सेगमेंट भी सोमवार को खासा व्यस्त रहेगा। केवी टॉयज इंडिया, प्रोडॉक्स सॉल्यूशंस और रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट्स के आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर एक साथ खुलेंगे। प्रोडॉक्स सॉल्यूशंस 27.6 करोड़ रुपये, केवी टॉयज इंडिया 37.74 करोड़ रुपये और रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट्स अपने अलग-अलग आकार के इश्यू लेकर आ रहे हैं। छोटे निवेशक और रिटेल ब्रोकरेज कंपनियां इन इश्यू पर खास नजर बनाए रखेंगी, क्योंकि एसएमई आईपीओ अक्सर लिस्टिंग डे पर बड़ा रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं।

इसके बाद 10 दिसंबर को बाजार में चार और आईपीओ दस्तक देंगे—नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज (871 करोड़ रुपये), पार्क मेडी वर्ल्ड (920 करोड़ रुपये), शिपवेव्स ऑनलाइन (53.53 करोड़ रुपये) और यूनिसेम एग्रीटेक (21.45 करोड़ रुपये)। हेल्थकेयर से लेकर लॉजिस्टिक्स और एग्रीटेक तक, इन आईपीओ में विभिन्न सेक्टरों की झलक देखने को मिलेगी। निवेशकों के लिए यह सप्ताह विविधता और अवसरों से भरा रहने वाला है।

11 दिसंबर को पेजन एग्रो इंडिया अपना एसएमई इश्यू लेकर आएगी, जिसके जरिए 70.23 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से आने वाला यह आईपीओ भी निवेशकों की दिलचस्पी का केंद्र बन सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में हाल के महीनों में कई कंपनियों ने लिस्टिंग के बाद मजबूत प्रदर्शन दिखाया है।

सप्ताह का सबसे बड़ा आकर्षण निस्संदेह 12 दिसंबर को लॉन्च होने वाला आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट का आईपीओ है। अनुमान है कि कंपनी बाजार से करीब 10,000 करोड़ रुपये जुटाएगी। यह आईपीओ ना केवल निवेशकों के लिए बल्कि वित्तीय बाजार के लिए भी बड़ी घटना साबित होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इस इश्यू के जरिए म्यूचुअल फंड उद्योग में बढ़ते भरोसे और पूंजी प्रवाह का संकेत भी मिलेगा। इसका प्राइस बैंड अगले सोमवार को घोषित होने की संभावना है।

पूरे सप्ताह बाजार में आने वाले ये 12 आईपीओ निवेशकों के लिए व्यापक अवसर लेकर आ रहे हैं। कुछ कंपनियाँ तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार का प्रतिनिधित्व करती हैं तो कुछ स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करती हैं। इस कारण यह सप्ताह न केवल आईपीओ प्रेमियों के लिए बल्कि संपूर्ण बाज़ार भावनाओं के लिए भी अत्यंत अहम माना जा रहा है।

आरपीएफ गांधीग्राम का सराहनीय कदम: ऑपरेशन अमानत के तहत यात्री का पर्स सकुशल लौटाया

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल अंतर्गत गांधीग्राम रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन अमानत के तहत ईमानदारी और तत्परता का एक सराहनीय उदाहरण सामने आया है। दिनांक 06.12.2025 (शनिवार) को गांधीग्राम के प्लेटफॉर्म संख्या 02 से सवारी गाड़ी संख्या 19204 (वेरावल–बांद्रा टर्मिनस) के रवाना होने के बाद ऑन ड्यूटी हेड कांस्टेबल श्री सुरेशभाई वाधेला को प्लेटफॉर्म पर एक महिला का पर्स पड़ा हुआ मिला। तत्पश्चात उन्होंने प्वाइंट्समैन को साथ लेकर पर्स को स्टेशन कार्यालय में लाया और ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर तथा रेल सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति में पर्स की जांच की गई।

पर्स में नकद 1880/-, एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल चार्जर सहित अन्य आवश्यक सामग्री पाई गई। उक्त पर्स को सुरक्षित रूप से कार्यालय में रखवा दिया गया। कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति श्री जितेन्द्र सेवेरा, निवासी अहमदाबाद, स्टेशन पर उपस्थित हुए और पर्स उनकी माता का होना बताया, जो उसी दिन ट्रेन संख्या 19204 के वातानुकूलित कोच बी-6 में यात्रा कर रही थीं। वैध जांच एवं सत्यापन के पश्चात पर्स तथा उसमें रखी समस्त सामग्री सही हालत में यात्री के पुत्र को लौटा दी गई। पर्स मिलने पर यात्री एवं उनके पुत्र द्वारा आरपीएफ गांधीग्राम का हृदय से आभार व्यक्त किया गया।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कहा कि हेड कांस्टेबल श्री सुरेशभाई वाधेला द्वारा ऑपरेशन अमानत के अंतर्गत किया गया यह कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है और रेलवे सुरक्षा बल की ईमानदारी, तत्परता तथा सेवा भावना को दर्शाता है।

कफ सीरप पीने से दो मासूमों की तबीयत बिगड़ी, एक की दर्दनाक मौत-दूसरा सैफई में जिंदगी से जंग लड़ रहा

(जीएनएस)। औरैया। नगला कहारन गांव में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, जहां खांसी की साधारण दवा देने के बाद दो मासूम भाइयों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। 18 महीने के रोहन की मौत हो गई, जबकि 9 महीने का सोहन गंभीर हालत में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में उपचाराधीन है। परिवार में खुशी का माहौल देखते ही देखते गहरे शोक में बदल गया।

घटना शुक्रवार की है। सहार क्षेत्र के पटना बेला निवासी सचिन कुमार अपने परिवार के साथ एक पारिवारिक मुंडन समारोह में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम के बाद वे अपनी साढ़ू के घर नगला कहारन में रुक गए। वहीं बच्चों को खांसी होने पर घर में मौजूद कफ सीरप कोफजिन उन्हें पिला दिया गया। यह दवा घर की महिला सदस्य अपने उपयोग के लिए लाई थी।

दवा देने के बाद नेहा ने बड़े बेटे रोहन को दूध पिलाया, लेकिन डकार दिलाए बिना दोनों बच्चों को सुला दिया। कुछ घंटे बाद जब बच्चे सोकर नहीं उठे तो परिजन घबरा गए और तुरंत सीएचसी बिधूना पहुंचे। डॉक्टरों ने रोहन को मृत घोषित कर दिया, जबकि सोहन की गंभीर स्थिति को देखते हुए सैफई रेफर कर दिया गया।

सीएचसी के चिकित्सक डॉ. प्रदीप सिंह ने बताया कि डकार न दिलाने के कारण दूध या दवा सांस नली में फंस जाने की आशंका है, जिससे एक बच्चे की जान चली गई और दूसरे की हालत गंभीर हो गई। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों में बेहद हल्का भी अवरोध जानलेवा साबित हो सकता है। स्थानीय मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि संभवतः कफ सीरप की मात्रा उम्र के हिसाब से अधिक दी गई होगी। छोटे बच्चों के लिए सामान्य डोज ढाई से तीन मिलीलीटर तक होती है।

घटना के बाद परिवार ने पोस्टमार्टम से इंकार कर दिया और रोहन का शव घर ले गए। गांव में मातम पसरा है और लोग हैरान हैं कि खांसी की एक साधारण दवा इतनी बड़ी त्रासदी कैसे बन गई।

बहुजन समाज मतदाता सूची पुनरीक्षण में सक्रिय हो, तभी बदलेगी राजनीतिक तस्वीर: मायावती

(जीएनएस)। लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने बहुजन समाज से अपील की है कि वे चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में पूरी सक्रियता से हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि यदि बहुजन समाज अपने राजनीतिक अधिकारों को मजबूत और सुरक्षित रखना चाहता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि हर योग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सही रूप से दर्ज हो।

दिल्ली स्थित अपने आवास पर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मायावती ने कहा कि दलित, पिछड़े और शोषित वर्ग आज भी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में अपने अधिकारों से वंचित महसूस करते हैं। उन्होंने ठहर कर कहा कि संविधान ने सभी को बराबरी का अधिकार दिया है, लेकिन इसके बावजूद सत्ता और संसाधनों तक पहुंच के रास्ते बहुजन समाज के लिए आज भी सरल नहीं हैं।

उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि करोड़ों बहुजन अभी भी उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब उन्हें अवसरों का वास्तविक लाभ मिलेगा—वह दिन जब वे न सिर्फ संख्या में, बल्कि राजनीतिक शक्ति के रूप में भी सम्मानित होंगे। मायावती ने कहा कि इस संघर्ष में वोट ही बहुजन समाज का सबसे प्रभावी हथियार है, और इस हथियार को मजबूत रखने के लिए सही मतदाता सूची अत्यंत जरूरी है।

उन्होंने कहा कि एसआईआर अभियान में प्रत्येक परिवार को जागरूक रहकर अपने-अपने नाम की पुष्टि करनी चाहिए। नए मतदाताओं, विशेषकर युवाओं, को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हों। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बहुजन समाज इस प्रक्रिया को हल्के में लेगा, तो राजनीतिक अधिकार धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाएंगे।

इधर, अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर प्रदेश के 12 मंडलों से बसपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में अनुयायी लखनऊ के 'डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल' पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहेब को नमन किया। नोएडा में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने भी श्रद्धांजलि दी। देशभर में जोन स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें संविधान निर्माता के प्रति श्रद्धा और बहुजन अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई।